प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2025

विषय:-आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला, निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1264/प्रोबे0(2)-244/2023(एम0-08.02.2023), दिनांक 08.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला, ग्राम-सहरावॉ, थाना-सोहरामऊ, जनपद-उन्नाव का निवासी है। बन्दी से दिनांक 24.03.1999 को प्रात: 6:30 बजे आपस में विवाद होने लगा। विवाद बढ़ जाने के कारण बंदी ने अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बाका, ईट से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 167/1999 में भा०द०वि० की धारा-147, 302/149, 325/149, 323/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 23.10.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2004 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 06.01.2025 तक अपरिहार 24 वर्ष, 04 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 30 वर्ष, 06 माह की सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 06.01.2025 तक 47 वर्ष, 03 माह, 26 दिन है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 22.12.2022 स्पष्ट नहीं है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि बंदी से दिनांक 24.03.1999 को प्रातः 6:30 बजे आपस में विवाद होने लागा। विवाद बढ़ जाने के कारण बंदी ने अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बाका, ईट से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 22.12.2022 स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला को

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेन्द्र (बन्दी सं0-14530) पुत्र श्री भोला, निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1280/2025/182(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
4- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।